भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2629

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना

2629. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा-केन्द्रित विनिर्माण और भारी उद्योग क्षेत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन-रहित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों और बजटीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और औद्योगिक संधारणीयता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उक्त पहलों के अपेक्षित योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दावणगेरे जिले और उसके आसपास संचालित औद्योगिक इकाइयों सहित कर्नाटक में स्थित उद्योगों को उक्त कार्यक्रमों से लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अवगत कराया है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना है तथा यह किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तदनुसार, एनडीसी फ्रेमवर्क दस्तावेज के अंतर्गत ऊर्जा-गहन विनिर्माण एवं भारी उद्योगों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट कार्य-योजना निर्धारित नहीं की गई है।

सरकार ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा संसाधन दक्षता से संबंधित विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से निम्न-कार्बन विकास को प्रोत्साहित कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) तथा जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) इन पहलों के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती हैं। कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के पात्र उद्योग, संबंधित स्कीमों के दिशानिर्देशों के अधीन उपलब्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समेकित उपायों के परिणामस्वरूप भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से सफलतापूर्वक पृथक किया है। भारत की प्रथम द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) के अनुसार, वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 37.38 प्रतिशत कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संचयी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिससे वर्ष 2030 के लक्ष्य को निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) अपने कार्बन पदचिह्न में कमी लाने के लिए निरंतर विभिन्न उपाय कर रहा है। इनमें अपनी विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि, गत 9 वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा संयंत्रों से लगभग 276 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44,000 से अधिक पौधे लगाकर कार्बन सिंक का सृजन, अपशिष्ट में कमी लाना तथा विद्युत, उद्योग एवं परिवहन क्षेत्रों के लिए दक्ष एवं निम्न-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों का विकास करना सम्मिलित है।

******